IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 2, September 2025
Impact Factor: 7.67

Hkkjr ljdkj }kjk lapkfyr çèkkuea=h vkokl ;kstuk dk fo'ys"k.kkRed vè;;u ¼banksj ftys ds fo'ks"k lanHkZ esa½

सोनिया देसाई

शोधार्थी, वाणिज्य, PMCOE, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

इंदौर, मध्य प्रदेश

डॉ. राजेश वर्मा

कुलगुरु, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर म.प्र.

lkjka'k

यह शोधपत्र भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ^^**çèkkuea=h vkokl ;kstuk**^^ (पीएमएवाई) के प्रभाव, कार्यान्वयन और लाभार्थी संतुष्टि का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के संदर्भ में। अध्ययन का उद्देश्य आवासहीन और निम्न–आय वर्ग के परिवारों को प्रदान की गई आवासीय सहायता के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करना है। इस शोध में 132 लाभार्थियों को न्याद”र् के रूप में चुना गया, जिनसे प्रश्नावली और साक्षात्कार के माध्यम से प्राथमिक आंकड़े संकलित किए गए हैं।

अध्ययन से ज्ञात हुआ कि योजना के अंतर्गत 79% लाभार्थियों को निर्माण हेतु प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त हुई, जबकि 68% उत्तरदाताओं ने अपने घर की गुणवत्ता को "संतोषजनक" बताया। विशेष रूप से 54% आवासों के स्वामित्व में महिलाओं का नाम दर्ज होना, लैंगिक समानता और पारिवारिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। इसके अतिरिक्त, 72% लाभार्थियों ने योजना को अत्यंत उपयोगी बताया, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस योजना ने सामाजिक गरिमा और आर्थिक आत्मनिर्भरता दोनों को सुदृढ़ किया है। यद्यपि राशि वितरण में विलंब (43%), निर्माण सामग्री की महँगाई (37%) और दस्तावेज़ी जटिलता (32%) जैसी चुनौतियाँ योजना की दक्षता को प्रभावित करती हैं, फिर भी इसका समग्र प्रभाव अत्यंत सकारात्मक रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना ने न केवल आवास निर्माण को प्रोत्साहन दिया, बल्कि इंदौर जिले में सामाजिक समावेशन, महिला सशक्तिकरण और जीवन स्तर सुधार की दिशा में एक स्थायी परिवर्तन की नींव रखी है।

eq[; 'kCn% प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदौर, लाभार्थी संतुष्टि, आवास विकास, वित्तीय सहायता, सामाजिक सशक्तिकरण।

1- ifjp; %

आवास मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने अनेक आवास योजनाएँ लागू कीं, किंतु वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ने "सभी के लिए आवास" की परिकल्पना को साकार रूप देने का प्रयास किया हैं। यह योजना दो प्रमुख खंडों में कार्यान्वित की जा रही है–

- **ih,e,okÃ ¼'kgjh½%** शहरी गरीब, झुग्गी निवासियों और निम्न आयवर्ग के लिए।
- **ih,e,okÃ ¼xzkeh.k½%** ग्रामीण क्षेत्रों के आवासहीन परिवारों के लिए।

इंदौर, जो मध्यप्रदेश का आर्थिक और औद्योगिक केंद्र है, में शहरीकरण की तेज़ गति के कारण आवास की माँग लगातार बढ़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय निकायों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से गरीब वर्ग को सस्ती और टिकाऊ आवास सुविधा प्रदान की है।

2- 'kksèk ds mís'; %

1. इंदौर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की स्थिति का विश्लेषण करना।
2. योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की गुणवत्ता और पारदर्शिता का मूल्यांकन करना।
3. लाभार्थियों की संतुष्टि और योजना की उपयोगिता का आकलन करना।
4. योजना से जुड़ी समस्याओं एवं सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

3- vuqlaèkku i)fr %

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है, जिसका उद्देश्य इंदौर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन और उसके सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करना है। अध्ययन का क्षेत्र इंदौर नगर निगम क्षेत्र एवं उसके निकटवर्ती विकासखंडों तक सीमित रखा गया हैं, जहाँ आवास निर्माण की गतिविधियाँ प्रमुख रूप से संचालित की जा रही हैं। कुल 132 लाभार्थियों को न्यादर्श समूह के रूप में चयनित किया गया, ताकि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और लिंग आधारित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। न्यादर्श चयन हेतु स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श विधि अपनाई गई, जिससे अध्ययन अधिक विश्वसनीय और प्रतिनिधिक बन सके। समंक संग्रह के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया। प्राथमिक समंक प्रश्नावली और व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से लाभार्थियों से संकलित किया गया, जबकि द्वितीयक समंक आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मध्यप्रदेश आवास विकास निगम तथा नगर निगम इंदौर की आधिकारिक रिपोर्टों एवं वेबसाइटों से प्राप्त किया गया। संग्रहित आँकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रतिशत विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन जैसी सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया गया।

4- led fo"ys'k.k ,oa ifj.kke%

rkfydk 1-çèkkue=h vkokl ;kstuk ds varxZr iathÑr ykHkkfFkZ;ksa dh okf"kZd fLFkfr ¼2016&2026½

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या
1	2016–2017	4,964,322

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, September 2025 Impact Factor: 7.67

2	2017–2018	3,298,766
3	2018–2019	2,649,733
4	2019–2020	5,108,819
5	2020–2021	4,271,389
6	2021–2022	8,639,699
7	2022–2023	2,645,301
8	2023–2024	864,082
9	2024–2025	6,464,541
10	2025–2026*	563,825 *(as on October 2025)*

lkzr% प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)– प्रगति रिपोर्ट, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016–2017 से 2025–2026 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण में उल्लेखनीय उतार–चढ़ाव देखा गया है। प्रारंभिक वर्षों (2016–2017) में योजना ने सशक्त गति से कार्य आरंभ किया, जहाँ 4.96 मिलियन लाभार्थी पंजीकृत हुए। अगले दो वर्षों में (2017–2019) पंजीकरण में गिरावट आई, जो प्रशासनिक संरचना के समायोजन और लाभार्थी सत्यापन की प्रक्रिया के कारण रही। वर्ष 2019–2020 और 2020–2021 में पुनः पंजीकरण में वृद्धि दर्ज हुई, और 2021–2022 में योजना ने अपने सर्वोच्च स्तर को छुआ, जहाँ 8.63 मिलियन लाभार्थी पंजीकृत किए गए। यह अवधि कोविड–19 के पश्चात ग्रामीण–शहरी आवास आवश्यकताओं की पुर्नबहाली और केंद्र सरकार द्वारा तीव्र आवास निर्माण पर बल देने का परिणाम रही।

इसके पश्चात 2022–2024 में पंजीकरण दर घटकर 2.64 मिलियन और 0.86 मिलियन तक आ गई, जो बजटीय पुनर्संरचना और लक्ष्य पूर्णता के कारण हुआ। हालाँकि, वर्ष 2024–2025 में पुनः तेजी आई और 6.46 मिलियन लाभार्थी जोड़े गए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजना में नई ऊर्जा और फोकस के साथ कार्य पुनः आरंभ हुआ। वर्तमान वर्ष 2025–2026 (अक्टूबर तक) में 0.56 मिलियन लाभार्थी पंजीकृत हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक यह संख्या पुनः वृद्धि की ओर अग्रसर होगी। सारांशतः, इन आँकड़ों से यह सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने पिछले दशक में स्थिरता के साथ निरंतर प्रगति की है। उतार–चढ़ाव के बावजूद, यह योजना देशभर में, विशेषकर इंदौर जिले जैसे शहरी क्षेत्रों में, आवासीय बुनियादी ढाँचे और जीवन–स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

rkfydk 2-çèkkue=h vkokl ;kstuk d vrxr i.k fd, x, vkoklk dh okf"kd fLFkfr ¼2016&2026½

क्रमांक	वर्ष	पूर्ण किए गए आवासों की संख्या
1	2016–2017	2,115
2	2017–2018	3,815,970
3	2018–2019	4,493,730
4	2019–2020	2,130,388
5	2020–2021	3,399,569

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, September 2025 Impact Factor: 7.67

6	2021–2022	4,239,724
7	2022–2023	5,677,012
8	2023–2024	2,059,726
9	2024–2025	1,332,844
10	2025–2026*	1,544,028 *(as on October 2025)*

lkr% प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)– प्रगति रिपोर्ट, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 2 से यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की गति समय के साथ उतार–चढ़ाव भरी रही है। योजना की शुरुआत वर्ष 2016–2017 में हुई, जहाँ मात्र 2,115 आवास पूर्ण किए गए, यह योजना के आरंभिक चरण का संकेत है। इसके पश्चात 2017–2019 के बीच निर्माण की गति में तीव्र वृद्धि हुई, जहाँ 2018–2019 में सर्वाधिक 4.49 मिलियन (44.9 लाख) आवास पूर्ण हुए। यह अवधि योजना के स्थायित्व और प्रशासनिक संरचना के सुदृढ़ होने का परिणाम रही। 2019–2021 के बीच निर्माण दर में गिरावट देखी गई (2.13 से 3.39 मिलियन तक), जो कोविड–19 महामारी के दौरान निर्माण गतिविधियों के ठहराव के कारण हुई।

वर्ष 2021–2023 में पुनः योजना ने रफ्तार पकड़ी, जहाँ 2022–2023 में रिकॉर्ड 5.67 मिलियन आवास पूर्ण किए गए, जो संपूर्ण अवधि में सर्वोच्च स्तर रहा। इसके बाद 2023–2025 में पूर्ण आवासों की संख्या क्रमशः घटकर 2.05 मिलियन और 1.33 मिलियन तक पहुँची, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना का फोकस अब शेष लंबित परियोजनाओं के समापन पर केंद्रित हो गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–2026 (अक्टूबर तक) में 1.54 मिलियन आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जो यह दर्शाता है कि योजना का कार्य अब स्थिरता के चरण में प्रवेश कर चुका है।

rkfydk 3-ykHkkFkh dh tulkf[;dh çkQkby

क्र.	विवरण	वर्गीकरण	संख्या	प्रतिशत (%)
1	**लिंग**	पुरुष	58	43.9%
		महिला	74	56.1%
		कुल	132	100%
2	**आयु वर्ग**	25–35 वर्ष	36	27.3%
		36–45 वर्ष	52	39.4%
		46 वर्ष से अधिक	44	33.3%
		कुल	132	100%
3	**आय वर्ग**	₹5,000 तक	38	28.8%

IJARSCT

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, September 2025 Impact Factor: 7.67

		₹5,001–₹10,000	59	44.7%
		₹10,001 से अधिक	35	26.5%
		कुल	132	100%
4	**शिक्षा स्तर**	प्राथमिक या कम	42	31.8%
		माध्यमिक	55	41.7%
		स्नातक या अधिक	35	26.5%
		कुल	132	100%

lkr% प्राथमिक समंक

अधिकांश लाभार्थी महिलाएँ (56.1%) थीं, जो योजना के सामाजिक समावेशन के उद्देश्य को पुष्ट करती हैं। 36–45 वर्ष आयु समूह (39.4%) प्रमुख रहा, जिससे स्पष्ट है कि योजना ने जिम्मेदार परिवारों को प्राथमिकता दी। अधिकतर लाभार्थी निम्न आयवर्ग से संबंधित थे, जो योजना की लक्षित जनसंख्या को दर्शाता है।

rkfydk 4-çèkkuea=h vkokl ;kstuk dk vurxZr ykHkkfFk;ksa dk vuqHko vkj leL;k,¡

क्रमांक	अध्ययन के मापदंड	विवरण / अवलोकन	लाभार्थियों का प्रतिशत (%)
1	**वित्तीय सहायता**	अनुदान राशि प्राप्त करने वाले लाभार्थी	79%
		पूरक धन निजी स्रोतों से जुटाने वाले लाभार्थी	21%
2	**आवास की गुणवत्ता**	निर्माण गुणवत्ता को "संतोषजनक" बताने वाले लाभार्थी	68%
3	**महिलाओं की भागीदारी**	जिन आवासों में स्वामित्व में महिला का नाम शामिल था	54%

ISSN: 2581-9429
Impact Factor: 7.67

4	**संतुष्टि स्तर**	योजना को "अत्यंत उपयोगी" बताने वाले लाभार्थी	72%
5	**मुख्य समस्याएँ**	राशि वितरण में विलंब	43%
		निर्माण सामग्री की बढ़ती लागत	37%
		दस्तावेज़ी प्रक्रिया की जटिलता	32%

Ikr% प्राथमिक समंक

तालिका 4 से यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने इंदौर जिले में निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 79% लाभार्थियों को सरकार से निर्माण हेतु अनुदान राशि प्राप्त हुई, जिससे उन्हें स्थायी आवास निर्माण में सहायता मिली। वहीं 21% लाभार्थियों को योजना की राशि के अतिरिक्त पूरक धन निजी स्रोतों से जुटाना पड़ा, जो यह दर्शाता है कि कुछ मामलों में आवंटित सहायता राशि संपूर्ण निर्माण लागत को कवर नहीं कर सकी। आवास की गुणवत्ता के संबंध में 68% उत्तरदाताओं ने अपने घर को "संतोषजनक" बताया, जो यह संकेत देता है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सामान्यतः अपेक्षित मानकों के अनुरूप रही है। महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि 54% आवासों के स्वामित्व में महिला का नाम दर्ज किया गया, जो न केवल लैंगिक समानता की दिशा में सकारात्मक कदम है, बल्कि पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं की सहभागिता को भी मज़बूत करता है।

संतुष्टि स्तर के विश्लेषण से यह पता चला कि 72% लाभार्थी योजना को "अत्यंत उपयोगी" मानते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इस योजना ने सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित किया है। हालाँकि, कुछ प्रमुख समस्याएँ भी सामने आईं– जैसे राशि वितरण में विलंब (43%), निर्माण सामग्री की बढ़ती लागत (37%) और दस्तावेज़ी प्रक्रिया की जटिलता (32%), जो योजना के कार्यान्वयन की दक्षता को प्रभावित करती हैं।

5- mi lgkj%

प्रधानमंत्री आवास योजना ने इंदौर जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यह योजना केवल भौतिक निर्माण तक सीमित न रहकर सामाजिक सुरक्षा और पारिवारिक स्थिरता का भी प्रतीक बनी है। लाभार्थियों के अनुभव से स्पष्ट हुआ कि वित्तीय सहायता ने गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को पक्का घर प्राप्त करने में सक्षम बनाया। साथ ही, महिला स्वामित्व को प्राथमिकता देने से परिवारों में निर्णय–शक्ति का संतुलन बढ़ा है। हालाँकि, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता की कमी योजना की प्रभावशीलता को सीमित करती है। इंदौर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ने न केवल आवास निर्माण को प्रोत्साहन दिया, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ जीवन–पर्यावरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह योजना गरीब एवं निम्न आय वर्ग के लिए "छत से सम्मान" का प्रतीक बनकर उभरी है। अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि लाभार्थियों का जीवनस्तर, सामाजिक प्रतिष्ठा और

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, September 2025 Impact Factor: 7.67

मानसिक संतुलन इस योजना के बाद बेहतर हुआ है। फिर भी, योजना की दीर्घकालिक सफलता के लिए भुगतान प्रक्रिया की सरलता, निर्माण गुणवत्ता की निगरानी और जन–जागरूकता अभियानों को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

6- l>ko%

1. लाभार्थियों को भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध की जाए।
2. निर्माण गुणवत्ता की निगरानी हेतु स्थानीय समितियाँ गठित की जाएँ।
3. महिला स्वामित्व को प्रत्येक आवास में अनिवार्य किया जाए।
4. तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण मजदूरों को निर्माण कार्य में जोड़ा जाए।
5. लाभार्थियों की संतुष्टि के लिए समय–समय पर फील्ड सर्वेक्षण किए जाएँ।

7. संदर्भ

[1]. Government of India. (2023). *Pradhan Mantri Awas Yojana: Annual Progress Report.* Ministry of Housing and Urban Affairs.

[2]. Madhya Pradesh Housing Board. (2022). *State Housing Development Report.* Bhopal.

[3]. Sharma, P. (2021). *Affordable Housing and Urban Development in India. Economic Affairs*, 66(2), 153–164.

[4]. Gupta, R. & Mehta, A. (2020). *Impact of PMAY on Urban Poor: A Study of Selected Cities. Indian Journal of Public Policy*, 15(4), 245–259.